IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैश्वीकरण का दलितों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

रोहित कुमार शोध छात्र

डा. रोचना मित्तल प्रोफेसर

राजनीतिक विज्ञान विभाग

शंभू दयाल कॉलेज, गाजियाबाद (उ. प्र.) भारत

संबंध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (उ. प्र.) भारत

वैश्वीकरण ने सभी राष्ट्रों पर बहुआयामी प्रभाव डाले हैं। वैश्वीकरण ने न सिर्फ इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को ही जोड़ने का कार्य किया है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता को भी बढ़ाया है। जिससे सभी देशों में व्याप्त प्राचीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों को खत्म करने में भी मदद मिली है। इन सभी परिवर्तनों से भारत में स्थापित प्राचीन ब्राह्मणिक सामंती व्यवस्था भी अत्यंत प्रभावित हुई। जिसका प्रभाव सदियों से प्रताड़ित दलित समाज पर भी पड़ा है। इस तरह वैश्वीकरण के पश्चात किस प्रकार और कितना परिवर्तन दलितों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में हुआ का निरीक्षण प्रस्तुत पत्र का उद्देश है।

Key words: खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, ब्रह्मणिक सामंती व्यवस्था, उपभोक्तावाद, बाजारवाद,

परिचय

दलितों की स्थिति में यदि सुधार किया जा सके तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? इस प्रश्न की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है तथा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है। ताकि भारतीय समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। आजादी के इतने सालों पश्चात भी दलितों की स्थिति में आशातीत परिवर्तन नही हो पाया है इसका मुख्य कारण भारतीय हिंदू समाज की सामाजिक, आर्थिक संरचना और रूढ़ीवादिता रही है। भारत में स्थापित जाति व्यवस्था न सिर्फ उच्चतर और निम्नतर का ही भेद बतलाती है बल्कि उत्पादन के साधनों पर किसका और कितना स्वामित्र होगा इसका भी निर्धारण करती है। जिसके तहत ही दलितों को संसाधनों में कोई भी हिस्सेदारी नही मिली है। समाज की मुख्यधारा में उनका आगमन आज भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। वर्तमान में भी जीवन के सभी क्षेत्रों में दलित अन्य जातियों से पिछड़े हुए और उनकी दया पर आश्रित हैं। संविधान द्वारा समानता का अधिकार, भेदभाव की मनाही और आरक्षण की व्यवस्था अवश्य ही की गई है लेकिन इन सुधारो को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए जरूरी और मूलभूत अहर्ताओं (सामाजिक स्वीकृति, आर्थिक सुदृढ़ता) के अभाव में दलित इन अधिकारों का समुचित उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। कानूनी और सामाजिक समानता को विश्वसनीय बनाने के लिए उसे समाज की मान्यता और स्वीकृति भी आवश्यक शर्त है, जिसके अभाव में कानूनी समानता मात्र एक दिवास्वप्न बनकर रह जाती है। इसलिए राजनीतिक और कानूनी बदलाव को विश्वस्त बनाने के लिए समाज में बदलाव लाना मुख्य शर्त है। इसके लिए समाज को अपनी रूढ़ीवादिता को छोड़ नए मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले भी भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनेक संतो, महात्माओं, समाज सुधारकों जैसे बुद्ध, ज्योतिबा फूले और पेरियार आदि ने प्रयास किए हैं, वे इस कार्य में कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन फिर भी हिंदू समाज अपनी ज्यादातर रूढ़ियों को खत्म करने में असमर्थ रहा है।

वैश्वीकरण जब भारत आया तो अपने साथ पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और बाजारवाद भी लाया जिसके चलते भारतीय जनमानस की प्रवृत्ति और सोच भी बदली है। जोती सेखोन(2000) आशा करती है कि जैसे–जैसे भारत पश्चिमी नीतियों के तहत और अधिक उद्योगीकृत और आधुनिक बनेगा तो समाजिक स्थिति को निर्धारित करने में जाति की बजाय वर्ग एक महत्वपूर्ण सूचक बन जाएगा। जोकि की सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, वर्तमान में जाति की भूमिका अवश्य ही कम होती जा रही है। पिछले दो तीन दशकों से भारतीय समाज और लोगो के व्यवहार में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। लोग अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, संस्कृति और तौर तरीकों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। प्रकाश एस. चितमन्नी कहते हैं, "वैश्विक जनसंख्या समान सामाजिक मूल्यों, आकांक्षाओं, दृष्टिकोणों और जीवन शैलियों को साझा करने के लिए करीब हो रही है"। नए मूल्यों को आत्मसात करने के लिए लोगों की सोच और प्रवृति में बदलाव की जरूरत होती है जिसकी पूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वयं के लाभ के लिए कर दी गई है। इन कंपनियों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारतीय

संस्कृति, लोगो के रहन सहन, भौतिकवादी सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बाजारू प्रवृति को बढ़ाना और भौतिकवाद का प्रसार करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। जिससे व्यक्ति का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना हो गया है, जिसके प्रभाव में धर्म को कम और भौतिक सुखों को अधिक महत्व दिया जानें लगा है। इसने जातिगत स्तरीकरण की बजाय वर्ग स्तरीकरण को बढ़ाया है जो की समाजिक स्तरीकरण की एक खुली व्यवस्था है जिसमे सामाजिक स्थिति जन्म के बजाय काबिलियत ,योग्यता और आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। गीतांजलि राठौड़ के शब्दों में,बाजारवाद के प्रभाव से सदियों से चली आ रही हमारी संस्कृति और विरासत खत्म होती जा रही है और हम एक नए वैश्विक ग्राम की संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसकी फौजें हैं जो बाजार की सर्वेसर्वा बनकर बाजार का बाजारूपान बढ़ाकर बाजारवादी संस्कृति को फैला रही हैं। बाजारवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारतीय जनमानस को इस स्तर तक प्रभावित किया है कि हम विदेशी मूल्यों, वस्तुओं और रहन सहन के गुलाम होते जा रहे हैं इसकी चपेट में आने से भारतीय अपनी वर्षों पुरानी रूढ़ियों को त्यागकर अधिक उदारवादी, पश्चिमी मूल्यों पर आधारित और विवेकशील जीवन जीने लगा है। इस प्रकार बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में दलितों के प्रति हो रहे अन्याय और भेदभाव पूर्ण व्यवहार में भी कमी आई है और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति बेहतर हुई है।

वैश्वीकरण के पश्चात दलित राजनीतिक मंच पर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। आरक्षण के आधार पर राजनीतिक पद प्राप्त कर लेने के बाद भी दलितों की ऊंची जाति के लोगो पर आर्थिक निर्भरता ने उन्हें नाम मात्र की शक्ति प्रदान की, आरक्षित सीटों पर भी ऊंची जाति के लोग अपने पिछलग्गू दलित नेताओं को जीत दिलाने में सफल हो जाते थे जिससे दलितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हों पाता था। दलितों के पास न तो सांगठनिक शिक्षा थी तथा न ही चुनावों में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन तथा संचार माध्यम ही थे जिससे की वो अपने विचारों को अपने लोगो तक पहुंचा सके। लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात उनकी इस स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। आर्थिक सुदृढ़ीकरण और संचार माध्यमों की उपलब्धता ने दलितों के राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्वीकरण के पश्चात संचार साधनों के सस्ता और सुलभ होने से दलित नेताओं को अपने लोगो के साथ सम्पर्क स्थापित करने में आसानी हुई। जिसके पश्चात् दलितों ने विभिन्न राजनितिक दलों और दबाव समूहों का निर्माण किया जो आज भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जो उनके बढ़ते राजनितिक प्रभाव और बढ़ते राजनीतिक ज्ञान को दर्शाता है। प्रस्तुत पत्र में हम वैश्वीकरण के प्रभाव में हो रहे सामजिक, आर्थिक और राजनितिक परिवर्तनों से दलितों के जीवन में हुए बदलावों को समझने हेतु निरिक्षण करेगे।

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और उसका दलितों पर प्रभाव

आजादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिससे 1990 तक भारत आर्थिक रूप से पिछड़ गया और अत्यधिक कर्ज में डूब गया । इस स्थिति से उभरने और ऋण प्रदान लिए विश्व बैंक ने भारत को नीतियों में बदलाव लाने के सुझाव दिए । जिसके परिणामस्वरूप भारत ने वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। इससे पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी जिसमे जमीदार जोकि ऊंची जाति से संबंध रखते थे दलितों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार और उनका आर्थिक शोषण किया करते थे। कई जगह दलित महिलाओं को शादी के बाद पहली रात जमींदार या पटेल के साथ गुजारनी पड़ती थी। ऐसा नही किए जाने पर उन्हें दंड भुगतना पड़ता था। नीची जाति से संबंध रखने के कारण और और आर्थिक तौर पर जमींदारों पर आश्रित होने के कारण दलित महिलाओं को ब्लातकार और हिंसा का शिकार होना पड़ता था। दलित जोकि ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे के पास रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध न होने कि स्थिति में इस शोषणकारी अवस्था से छुटकारा पाने में असमर्थ थे।

वैश्वीकरण के आविर्भाव और उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों अपनाए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण अपने साथ नई संभावनाएं, नए रोजगार और नई आर्थिक नीतियां लाया जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के पुराने ढांचे को को पूरी तरह बदल दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, आयत–निर्यात में अत्यधिक वृद्धि, विदेशी बाजारों तक आसान पंहुच तथा हाल ही में सूचना उद्योग में हुई अत्यधिक उन्नति ने विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। प्राथमिक क्षेत्र की बजाय द्वितीय और सेवा क्षेत्र का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान अधिक तेजी से बढ़ा है। वस्तुओं, सेवाओं और श्रम का सीमा पार आदान प्रदान आसान और अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकसित होने से, घरेलू और विदेशी कंपनियों ने तेजी से वृद्धि की और अपनी उत्पादन क्षमता कई गुणा बढ़ा दी, जिससे रोजगार के नए अवसरों और क्षेत्रों का सृजन हुआ। इंटरनेट और सूचना उद्योग की बदौलत एक नई अवधारणा 'घर से कार्य'(वर्क फ्रॉम होम) ने भी व्यक्ति को विश्व बाजार से सीधे तौर पर जोड़ दिया है जिसमे आप घर बैठे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीद और बिक्री की साइटों से आप घर बैठे ही विश्व भर से अपने लिए कोई भी समान मंगवा सकते हैं और अपने घर पर तैयार सामान को बेच भी सकते जिससे हम सभी विश्व विश्व बाजार का एक अंग बन गए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं की वैश्वीकरण के पश्चात रोजगार के क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। डॉ आंबेडकर द्वारा यह विचारा गया था कि व्यवसायों के पुनः समायोजन की अनुमति न देने से, जाति देश में देखी जाने वाली अधिकांश बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है (अंबेडकर एन. जाति की) जाति व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति के कार्यों को जन्म से निर्धारित कर दिया जाता था जिससे बाहर जाकर कार्य करने की मनाही थी जिस वजह से भी दलित को भुखमरी की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात दलितों के लिए

भी नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उन्हें अपने पपरंपरागत कार्यों से निजात मिली है। जिससे उनके शोषण और उनके प्रति जमीनदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार में कमी आई है। प्रतियोगी बाजार व्यवस्था से ज्यादातर वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। विदेशों से आए सस्ते सामान ने भारतीय बाजारों को भर दिया। जिससे दलितों के लिए इन्हें खरीदना आसान हुआ। अब वे कम कीमत पर अपनी रोजमर्रा की वस्तुएं खरीद सकते थे और अपने जीवन जीने के तरीकों को अन्य जातियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह वैश्वीकरण ही है जिसके कारण मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी घर–घर और अत्यधिक काम कीमत पर मिल जाती है।

2 सामाजिक परिवर्तन और दलितों पर प्रभाव

वैश्वीकरण ने सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों को ही आपस में नही जोड़ा है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों और आचार विचार के आदान प्रदान को भी बढ़ाया है। आज पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम में तब्दील होता जा रहा है और सभी राष्ट्र इस वैश्विक ग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। विश्व के सभी राष्ट्र आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि संसार के किसी भी कोने में होने वाली घटना सभी राष्ट्रों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रभावित करती है। इस प्रकार विश्व में हो रहे उदारवादी बदलावों का प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा है।

भारतीय सामाजिक संरचना जो सदियों से हुई उथल पुथल के बावजूद भी मुख्यता अपरिवर्तित ही रही है वैश्वीकरण के उदय ने इसकी जड़ों को हिला कर रख दिया। वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू सामाजिक संरचना जो एक बंद व्यवस्था थी, ने वैश्विक मूल्यों को अपनाना शुरू कर दिया जिससे इसकी कठोरता मे कमी आती चली गई तथा वर्ग आधारित सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा मिला। जोती सेखोन के शब्दों में स्तरीकरण की वर्ग प्रणाली को स्तरीकरण की एक खुली प्रणाली के उदाहरण के रूप में देखा जाता है जिसमें आर्थिक स्थिति सामाजिक स्तर या स्थिति का आधार है इसलिए इस प्रणाली में यह है कि किसी की भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। बाहरी विश्व से जुड़ने के कारण हिंदू समाज भी समानता, स्वतंत्रता के उदारवादी मूल्यों को अपनाकर उदारवादी स्वरूप का बनता जा रहा है, जिससे जातिगत भेदभाव की जगह वर्ग आधारित भेदभाव में वृद्धि होती जा रही है। आज दलितों और अन्य जातियों के मध्य सामाजिक समरसता बढ़ीं है, सभी एक दूसरे के घर बिना किसी भेदभाव के आपसी संबंधों को प्रेम के साथ निभा रहे हैं। ऊंच–नीच, छूत–अछूत की संकीर्ण मानसिकता समाप्त होने के कगार पर है तथा सामाजिक जीवन में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दलितों को भी समान हिस्सेदारी के आधार पर शामिल किया जा रहा है। ऊंची जाति के लोग भी दलितों के यहां जाने से संकोच नही करते हैं। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि और समाज द्वारा इसकी स्वीकृति भी बदलते सामाजिक परिवेश को दर्शा रही है। यह सब वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि आज दलितों के प्रति हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति समाज में

जागरूकता फैली है। विश्वपटल पर भी दलितों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी है और उनके चहुंमुखी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दलितों के शैक्षिक और रहन सहन के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार की प्रथा में वृद्धि भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है जिसने समुदाय की भावना के बजाय व्यक्तिगत पहचान को अधिक महत्व प्रदान किया है, ने भी जातिगत भेदभाव की व्यवस्था पर प्रहार किया है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार के अनेक कारकों को जन्म दिया जिससे समाज में उनकी स्थिति बेहतर हुई है।

३. धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन

भारतीय जन जीवन और हिंदू समाज में धर्म और धर्म परायणता का विशेष महत्व रहा है जिसके लिए महाभारत जैसा युद्ध तक हुआ। किसी भी कीमत पर धर्म को न छोड़ना हिंदुओं की रीत रही है, इस धर्म परायणता का सबसे अधिक नुकसान दलितों को उठाना पड़ा है। हिदू धर्म में सभी के लिए कार्यों को नियत कर दिया गया है जिनसे बाहर जाकर कार्य करना धर्म के विरुद्ध कार्य करने जैसा है। हिंदू धर्म में दलितों के लिए ऐसे नियम बनाए गए जिनसे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास अवरूद्ध हो गया और उनका जीवन स्तर गिरता चला गया। उनकी इस स्थिति में सुधार के सभी रास्ते बंद कर दिए गए जिससे वे हजारों सालों तक भी अपनी गुलामी से आजादी नहीं पा सके। उनका कार्य बिना किसी हिचकिचाहट के उपरी तीन वर्णों की सेवा करना था। उसके लिए शिक्षा ग्रहण करना, संपत्ति एकत्र करना मना था, और भी बहुत से प्रतिबंध लगाए गए जिससे उसका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। दलित पूरी तरह से अन्य जातियों पर निर्भर हो गए जोकि उनका भरपूर शोषण और उनके प्रति अत्याचार किया करते थे।

हिंदू धर्म में दलितों को अछूत माना जाने लगा जिससे उनके छूने मात्र से ही कोई अपवित्र हो सकता था। उन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने की मनाही थी। कई जगह उन्हें सिर्फ रात्रि और कड़ी दोपहर में ही बाहर निकलने का नियम था ताकि उनकी परछाई पड़ने से कोई अपवित्र न हो जाए। उनके गले में चलते वक्त थूकदान डालने का नियम था जिससे की वो रास्ते में न थूके जिस पर पैर पड़ने से कोई अपवित्र हो सकता था, उन्हें चलते समय अपनी कमर पर झाड़ बांधना अनिवार्य था ताकि उनके कदमों के निशान उनके साथ ही मिट जाएं। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा हिंदू धर्म के नियमो का पालन करना दलितों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जितना अधिक एक हिंदू अपने धर्म के प्रति कट्टर होगा उतना अधिक कष्ट एक दलित को सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं का हिंदू धर्म के नियमो में विश्वास कम करना ही दलितों के विकास, आजादी और गरीमामय जीवन की गारंटी दे सकता है। अंबेडकर जी ने भी कहा है कि "उस धार्मिक धारणा को नष्ट किए बिना जाति को तोड़ना संभव नहीं है जिस पर जाति व्यवस्था आधारित है।"

वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय वैश्विक मूल्यों और संस्कृति को अपना रहे हैं जिससे भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज व्यक्ति धर्म की बजाय धन उपार्जन को अधिक महत्व देने लगा है। भौतिक सुखों को अधिक से अधिक पूर्ति लोगों का लक्ष्य बन गई। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक वैविध्य स्थापित करने की बजाय सांस्कृतिक समरूपता को स्थापित करने का कार्य है, लेकिन साथ ही आर्थिक विषमता को भी बढ़ाया है। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है जिससे लोगो ने नए मूल्यों, आचार विचार के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया है। बाजारवादी संस्कृति के चलते लोग अपनी संस्कृति और विरासत को भूल रहे हैं और एक वैश्विक भौतिकवादी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं, जिसमे अमीर गरीब के भेदभाव की जगह किसी अन्य प्रकार के भेदभाव को गौण समझा जा रहा है। आज सभी धार्मिक अंधविश्वास की जगह विवेक पर आधारित जीवन जीने लगे हैं और उन धार्मिक नियमो और मूल्यों को त्याग दे हैं जो नैतिकता के विरुद्ध और अविववेकपूर्ण हैं। इसलिए वैश्वीकरण के पश्चात जाति आधारित भेदभाव कम होता जा रहा है और आर्थिक विषमता पर आधारित भेदभाव में वृद्धि हुई है। इससे दलितों को जाति आधारित भेदभाव से अवश्य ही आजादी मिली हैं। तथापि गरीबी से मुक्ति उनके लिए अभी भी दूर है जिसके चलते वह न तो अपना ही समुचित विकास कर सकते हैं और न ही देश के विकास में खास योगदान दे सकते हैं।

वैश्वीकरण और दलितों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दलितों को शिक्षा, संपत्ति, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रखा गया जिससे उनका विकास अवरूद्ध हो गया और वह पिछड़ेपन का शिकार हुए। आजादी के बाद विभिन्न कानूनो तथा आरक्षण की व्यवस्था से दलितों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ फिर भी यह आंकड़ा बहुत कम था अन्य जाति के लोगो पर आर्थिक निर्भरता और सामंती अर्थव्यवस्था ने उनकी दयनीय स्थिति को बनाए रखा। ज्यादातर दलित समाज अभी भी दरिद्रता और शोषण को झेल रहा था।

व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत अधिक योगदान होता है। अरस्तू दास प्रथा का औचित्य इसी आधार पर उचित ठहराता है कि वे यूनानी नगर राज्य के नागरिकों को राज्य के कार्यों में भाग लेने के लिए सहायता और समय प्रदान करते हैं। दास नागरिकों को भौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति करते है जिससे वे चिंता मुक्त होकर राज्य के कार्यो में भाग ले सकें। यदि कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही सक्षम नही है तो उससे किस प्रकार हम यह आशा कर सकते हैं कि वह राज्य के कार्यों में समुचित और स्वतंत्रता पूर्ण भागीदारी निभाए। यही वजह दलितों की पिछड़ी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के कारणों की ओर संकेत करती है। दलित सदियों से ही गुलामी और गरीबी की ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ है जिससे छुटकारा पाने के लिए न तो उसके पास पर्याप्त समय है, न शिक्षा और न पर्याप्त संसाधन ही हैं वह सदियों से सिर्फ अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही संघर्षरत

है जिसमे वह आज भी सफल नही हो पाया है। ज्यादातर दलित समाज आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है।

वैश्वीकरण ने दलितों के स्थिति में परिवर्तन के अनेक कारणों को जन्म दिया जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर हुई। जैसे अन्य जाति के लोगो या जमींदारों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई, आर्थिक स्थिति में सुधार, दलित नेताओं का उभरना, अपना अच्छा बुरा विचारने के लिए समय की उपलब्धता, संचार साधनों के सस्ता और सुलभ होने से अपने लोगो के साथ विचारों के आदान प्रदान में आसानी, भेदभाव में कमी आने से बढ़ता आत्मविश्वास, वैश्विक समुदाय से जुड़ने से बढ़ा ज्ञान आदि ने दलितों की राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया और संचार के साधनों में हुई तरक्की और सुलभता ने दलितों को राजनीतिक रूप से संगठित होने में भारी योगदान दिया है। आज दलित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है जो उनके राजनीतिक सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दलितों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है जिससे वो अपनी मांगों और अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को अधिक मजबूती से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इन सभी बदलावों के परिणामस्वरूप ही भारतीय राजनीतिक गलियारे में एक नए युग का आरंभ हुआ है। बीएसपी, बामसेफ, भीम आर्मी आदि राजनीतिक दल और दबाव समूह दलितों के बढ़ते राजनीतिक ज्ञान और परिपक्वता को दर्शाता है। यद्यपि इसमें अभी भी काफी वक्त लगने की संभावना है। दलित की आर्थिक स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है जो उसकी सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी को अवरूद्ध करती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है की वैश्वीकरण ने दलितों की जिंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिससे वो एक गरिमामय जीवन जीने के काबिल हुए। आज दलित को जीवन के सभी क्षेत्रों सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के अवसर बिना जातीय भेदभाव के प्राप्त हुए हैं। सदियों बाद दलित स्वतंत्र माहौल में सांस ले रहा है जिसका उसने भरपूर प्रयोग किया है और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन इन सब परिवर्तनों से हमे यह नही समझ लेना चाहिए की वैश्वीकरण ने दलितों के स्थिति में सिर्फ सकारात्मक ही प्रभाव डाले हैं बल्कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जिनका वर्णन यहां नही किया गया है उन्हें भी ध्यान में अवश्य ही रखा जाना चाहिए, तत्पश्चात ही वैश्वीकरण के प्रभाव का सही मूल्यांकन संभव है। पूंजीवाद के बढ़ते प्रसार ने जातीय भेदभाव को अवश्य ही कम किया है लेकिन अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को और अधिक गहरा किया है। जातिगत भेदभाव की जगह दलित अब आर्थिक शोषण का शिकार होता जा रहा है जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य की भूमिका अवश्यंभावी है। लेकिन वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को क्षति पहुंचाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश

की नीतियों को अपने अनुसार ढालने की क्षमता रखती हैं जिससे राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में कमी आई है, इसका दलितों पर अवश्य ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। MNCs में नोकरी पाने के लिए आपके पास विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है जिन्हे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन दलितों के पास नही होता है इसलिए वैश्वीकृत जगत में गरीबी दलितों के लिए एक मुख्य बाधक साबित हुई है।

References

(1). ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स सुज़ैन बर्जर, राजनीति विज्ञान विभाग, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स 02139;

(2). कास्ट एंड क्लास अध्याय 8 IGNOU डॉ. प्रशांत खत्री, सहायक प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

(3). इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी: एन ओवरव्यू, प्रकाश एस.कट्टीमणि सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलगावी, कर्नाटक, भारत

(4). बाजारवाद का समाज पर प्रभाव,:एक अध्ययन गीतांजलि कंवर राठौड़ प्रथम अध्याय३ पृष्ठ 28

(5). ग्लोबलाइजेशन एंड द दलित, कुमार ज्वाला, द इंडियन जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस

(6). अछूत , मूलक राज आनंद, 1947.

(7). रि-थिंकिंग इनिक्वलिटी: दलित इन उत्तर प्रदेश इन द मार्केट रिफॉर्म एरा , दावेश कपूर, चंद्रभान प्रसाद, डी श्याम बाबू, Economic and Political weekly

(8). झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि , Radhakrishan Prakashan

(9). जाति का विनाश , डा. बी आर अम्बेडकर , पेज 68 fingerprint publication

(10). आधुनिकता के आईने में दलित, अभय कुमार दूबे। Vani Prakashan

(11). मॉडर्न इंडिया। जोती सेखोन. Mc Grow hill publication 1999.